कृषि उत्पादों का उत्पादन और खपत

325. **श्री नेरश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान देश में विभिन्न कृषि उत्पादन की तुलना में उनकी खपत क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में स्थिति का कोई राज्य-वार आकलन किया है;

(ग) क्या खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता/खपत को बनाये रखा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता/खपत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (घ) 1997 तथा 1998 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों का उत्पादन तथा उपलब्धता/मनुष्यों द्वारा की जाने वाली खपत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)** हाल के वर्षों में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 171 से 187 कि.ग्रा० की सीमा में कायम की गई है। खाद्यान्नों की उपलब्धता/खपत का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

विवरण

खाद्यान्नों का उत्पादन तथा उपलब्धता/मनुष्यों द्वारा की जाने वाली खपत

(मिलियन मी० टन में)

जिंस	वर्ष	उत्पादन	खपत
चावल	1997	81.73	76.92
	1998 (पी)	82.30	75.85
गेहूं	1997	69.35	61.70
	1998 (पी)	65.90	53.96
अनाज	1997	185.19	164.19
	1998 (पी)	179.36	152.77
दालें	1997	14.25	13.08
	1998 (पी)	13.07	11.70
खाद्यान्न	1997	199.44	177.27
	1998 (पी)	192.43	164.47

गंगा के जल द्वारा भूक्षरण

326. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश एवं बिहार में गंगा नदी के जल से होने वाले भूक्षरण की समस्या के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने अध्ययन किए हैं और गंगा घाटी के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु इन्हें घाटी वाले सभी राज्यों को भेजा गया

है। इन व्यापक योजनाओं में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में किए जाने वाले विशिष्ट अपरदन विरोधी निर्माण कार्यों के लिए सुझाव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में मात्र गंगा नदी के कारण हो रही अपरदन की समस्या के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट अध्ययन नहीं किए गए हैं।

Foodgrain production

327. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that foodgrain output in 1998-99 is likely to fall short of target of 200 million tonnes;

(b) if so, what was total foodgrain production during the last 3 years, till date, group-wise;

(c) what are the reasons for fall of Government's target of doubling foodgrain production over the Ninth Plan period; and

(d) whether Government would be able to meet demand of foodgrains of all sectors in the country indicating the concrete steps taken so far to increase the foodgrains production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) The total foodgrain production during last three years and during current year by major crop groups is as under:

(million tonnes)

Crop Group	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
Rice	76.98	81.73	82.30	82.23
Wheat	62.10	69.35	65.90	69.13
Coarse Cereals	29.03	34.11	31.16	29.91
Cereals	168.11	185.19	179.36	180.47
Total Pulses	12.31	14.25	13.07	14.78
Total Foodgrain	180.42	199.44	192.43	195.25

(c) The Government does not envisage doubling foodgrain production during the Ninth Plan period. The plan is to double the food production in next ten years.

(d) In order the increase production of foodgrains, the Government is implementing crop specific centrally sponsored schemes/programmes under which incentives are provided to farmers for use of quality seeds and location specific high yielding/hybrid varieties, application of integrated pest management, propagation of scientific water management including micro irrigation, improved farm implements etc. Besides, field demonstration on farmers holdings including training of farmers and farm labourers are organised for effective transfer of technology. Further, under the national agenda for governance, the Government has given fresh thrust to double the food production in next ten years adopting regionally differentiated growth strategies, creation of farming infrastructure and more efficient use of resources. With the concerted efforts being made, it would be